



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, २२ नवम्बर, १९९५/१ अप्रहायण, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी (अंग्रेजी) अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-२, २२ नवम्बर, १९९५

संख्या एल० एल० आर० डी० (६) १४/९५-लेजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २०० के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख २१-११-९५ को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश

आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन विधेयक, 1995) (1995 का 12) को 1995 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 1995

(राज्यपाल द्वारा तारीख 21 नवम्बर, 1995 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का 7) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 1995 है । संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (घ घ) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:— धारा 2 का संशोधन ।

“(घ घ) “विशेषज्ञ समिति” से इस अधिनियम की धारा 12-क के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;” ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण जोड़े जाएंगे, अर्थात्:— धारा 5 का संशोधन ।

“परन्तु संरचनात्मक डिजाइन से सम्बन्धित प्राक्कलन, योजना (प्लान) विनिर्देश, सामग्री की क्वालिटी, सुरक्षा की बातें (फैक्टर), भार की संगणना का ढंग, उनके अनुरूप होंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित किए गए हैं और सम्यक् रूप से अहित संरचना इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए “अहित संरचना इंजीनियर” से ऐसी अर्हताएं और अनुभव, जो विहित की जाएं, रखने वाला स्नातक इंजीनियर अभिप्रेत है ।”

4. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) के खण्ड (xvi) में, “और न्यूनतम” शब्दों का लोप किया जाएगा । धारा 6 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) में,— धारा 10 का संशोधन ।

(i) खण्ड (क) में “उसने” के पश्चात् किन्तु शब्द “आकाशी” से पूर्व “और विशेषज्ञ समिति ने भी” शब्द रखे जाएंगे ; और

(ii) खण्ड (ड) में “उसके विचार में” शब्दों के पश्चात् किन्तु “आकाशी” शब्द से पूर्व “और विशेषज्ञ समिति के विचार में भी” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 11 का
संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

- (क) उप-धारा (1) में, शब्द “राज्य सरकार” के पश्चात् और “आकाशी” शब्द के पूर्व “स्नातक (यान्त्रिक) इंजीनियरों” में से जो अधिशाषी अभियन्ता की पंक्ति से नीचे के न हों” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और
- (ख) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं (2) और (3) रखी जाएंगी, अर्थात्:—
- “(2) निरीक्षक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या के अधीन उपबन्धित किए जाएं। ऐसे निरीक्षक का समय-समय पर ऐसे रज्जुमार्गों का निरीक्षण करना और यह अवधारित करना भी कर्तव्य होगा कि क्या वे ठीक स्थिति में निर्मित किए गए हैं और रखे गए हैं तथा उनको, प्रयोग करने वाले व्यक्तियों और सर्वसाधारण को पूरी सुरक्षा और सुविधा के अनुसार सही तौर पर इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत रूप में चलाया जा रहा है :

परन्तु निरीक्षक रज्जुमार्ग और इसके अनुलग्नकों का,—

- (i) जहां मनुष्यों को तीन मास में कम से कम एक बार ले जाया जाता है, वहां और
- (ii) जहां पशुओं और माल को छः मास में कम से कम एक बार ले जाया जाता है, वहां निरीक्षण करेगा।

- (3) राज्य सरकार अन्य अधीनस्थ अधिकारियों और सेवकों को भी ऐसे पदनामों से नियुक्त कर सकेगी और उन्हें ऐसी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य समनुद्देशित कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ”।

धारा 12-क
का अन्तः-
स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 12-क जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“12-क. विशेषज्ञ समिति.—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आकाशी रज्जुमार्ग के डिजाइन, स्थापन और परिचालन का ऐसा ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की ऐसी संख्या से गठित और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाएं, एक या अधिक विशेषज्ञ समितियां गठित कर सकेगी।

(2) विशेषज्ञ समिति का,—

- (i) अधिनियम के प्रशासन से सम्बन्धित किसी विषय की बाबत और निम्नलिखित की बाबत भी—

- (क) किसी आकाशी रज्जुमार्ग के डिजाइन, परिनिर्माण अथवा स्थिति या उससे सम्बद्ध किसी कार्य ;

- (ख) किसी रज्जुमार्ग में परिवर्धन अथवा परिवर्तन या वन्द करने ;
- (ग) किसी रज्जुमार्ग के स्वरूप या उसके प्रयोग के ढंग के परिवर्तन में, राज्य सरकार और निरीक्षक की सहायता करना और परामर्श देना कर्तव्य होगा;
- (ii) रज्जुमार्ग और अनुलग्नकों के,—
- (क) इस अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन इसके परिचालन के लिए मन्जूरी देने से पूर्व, आरम्भिक स्तर पर ;
- (ख) तत्पश्चात् वर्ष में कम से कम एक बार आकाशी रज्जुमार्ग और अनुलग्नकों का ; और
- (ग) ऐसे अन्य अवसरों पर जैसे राज्य सरकार द्वारा निदिष्ट किए जाएं ;
- यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण का संचालन करना कि रज्जुमार्ग सार्वजनिक यातायात के लिए उपयुक्त है और इसके उपयोग में कोई संकट अन्तर्बलित नहीं है” ।

8. मूल अधिनियम की धारा 13 में—

धारा 13 का संशोधन ।

- (i) शीर्षक में शब्द “निरीक्षकों” के पश्चात् और शब्द “को” से पूर्व “और विशेषज्ञ समिति” शब्द जोड़े जाएंगे ; और
- (ii) शब्द “निरीक्षक” से पूर्व “यथास्थिति,” और “निरीक्षक” शब्द के पश्चात्, “या विशेषज्ञ समिति के सदस्यों” शब्द जोड़े जाएंगे ।

9. मूल अधिनियम की धारा 18 में, “और न्यूनतम” शब्दों का लोप जा जाएगा ।

धारा 18 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 20 का प्रतिस्थापन

“जब आकाशी रज्जुमार्ग के कार्यकरण के अनुक्रम में कोई दुर्घटना हो जाए तो, संप्रवर्तक अनावश्यक विलम्ब के बिना दुर्घटना की सूचना राज्य सरकार और निरीक्षक को भेजेगा ; और संप्रवर्तक का आकाशी रज्जुमार्ग के उस स्टेशन का भार-साधक सेवक जो उस स्थान के निकट हो जहां दुर्घटना हुई है, या जहां कोई स्टेशन नहीं है वहां आकाशी रज्जुमार्ग के उस खण्ड के संप्रवर्तक का भार-साधक सेवक जिसमें दुर्घटना हुई है ; यथासम्भव न्यूनतम विलम्ब के, उस जिला के मजिस्ट्रेट को जिसमें दुर्घटना हुई है और उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर यह हुई है या ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को जिसे सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, दुर्घटना की सूचना देगा और यदि दुर्घटना में मानव जीवन की हानि हुई हो या किसी मानव को गम्भीर शारीरिक क्षति पहुंची हो, तो उसकी सूचना निकटतम औषधालय को भी भेजेगा” ।

धारा 20-क
का अन्तः-
स्थापन।

11. मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 20-क जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“20-क. बचाव कार्य:—यदि किसी बचाव कार्य के दौरान राज्य सरकार कोई व्यय उपगत करती है तो, संप्रवर्तक, राज्य सरकार द्वारा उपगत व्यय संदत्त करने के लिए दायी होगा और यदि संप्रवर्तक सम्पूर्ण या इसके भाग को संदत्त करने में असफल रहता है तो वह भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा”।

धारा 27 का
संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (1) में खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ड ड) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(ड ड) रज्जुमार्ग के चलाने और अनुरक्षण के लिए नियोजित कर्मचारीवृन्द की अर्हताएं विनियमित करना;”।

धारा 32 का
संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) में,—

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (क), (क क) और (क क क) रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(क) धारा 5 के अधीन संरचनात्मक इंजीनियर की अर्हताएं और अनुभव;

(क क) धारा 11 के अधीन नियुक्त निरीक्षक की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य;

(क क क) धारा 12-क के अधीन विशेषज्ञ समिति का गठन और इसके सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें, अर्हताएं और अनुभव;” और

(ii) खण्ड (घ) में, “और न्यूनतम” शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 33 का
संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 33 में, “200” अंक के स्थान पर “पांच हजार” शब्द और “50” अंक के स्थान पर “पांच सौ” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 36 का
संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 36 में, विद्यमान धारा को उप-धारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (2) जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) यदि संप्रवर्तक धारा 33 में रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में उल्लिखित किसी बात को, इस आशय से या यह जानते हुए कि ऐसे कार्य या लोप से आकाशी रज्जुमार्ग पर यात्रा कर रहे या उस पर होने वाले किसी व्यक्ति को खतरे की संभावना है, करेगा या नहीं करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक मास से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा”।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 13 of 1995.

**THE HIMACHAL PRADESH AERIAL ROPEWAYS
(AMENDMENT) ACT, 1995**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 21ST NOVEMBER, 1995)

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Act, 1995. Short title.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (hereinafter called the principal Act), after clause (d), the following clause (dd) shall be added, namely:— Amendment of section 2.

“(dd) “Expert Committee” means a Committee constituted under section 12-A of this Act;”.

3. In section 5 of the principal Act, the following proviso and Explanation shall be added, namely:— Amendment of section 5.

“Provided that the estimates, plans, specifications relating to the structural designs, quality of material, factors of safety, method of computing stresses shall be in conformity with those as laid down by the Bureau of Indian Standards and shall be duly certified by a qualified structural Engineer.

Explanation.—For the purposes of this section a “qualified structural Engineer” means a graduate Engineer having such qualifications and experience as may be prescribed.”

4. In section 6 of the principal Act, in sub-section (4), in clause (xvi), the words “and minimum” shall be omitted. Amendment of section 6.

5. In section 10 of the principal Act, in sub-section (1),— Amendment of section 10.

(i) in clause (a), for the words “that he has made a careful inspection”, the words “that he as well as the Expert Committee has made careful inspections” shall be substituted; and

(ii) in clause (e), after the words “that in his opinion”, the words “as well as in the opinion of Expert Committee” shall be inserted.

6. In section 11 of the principal Act,—

Amendment of section 11.

(a) in sub-section (1), after the words “Inspectors of aerial ropeways”, the words “out of Graduate (Mechanical) Engineers,

not below the rank of an Executive Engineer" shall be inserted; and

- (b) for sub-section (2), the following sub-sections (2) and (3) shall be substituted, namely:—

“(2) The Inspector shall exercise such powers and perform such functions and duties as may be provided by or under the provisions of this Act. It shall also be the duty of such Inspector, from time to time, to inspect such ropeways and to determine whether they are constructed and maintained in a fit condition and working properly to the entire convenience and safety of the persons using them and of the general public and consistent with the provisions of this Act:—

Provided that the Inspector shall inspect the ropeway and its appurtenances,—

- (i) where human beings are carried, at least once in three months; and
 - (ii) where animals and goods are carried, at least once in six months.
- (3) The State Government may also appoint other subordinate officers and servants with such designations and assign to them such powers, duties and functions as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.”

Insertion of
section 12-A.

7. After section 12 of the principal Act, the following section 12-A shall be added, namely:—

“12-A. Expert Committee.—(1) The State Government may, by notification in the official gazette, constitute one or more Expert Committees consisting of such number of persons, having such knowledge and experience in design, setting up and operating aerial ropeways, and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) It shall be the duty of the Expert Committee,—

- (i) to aid and advise the State Government and the Inspector in regard to any matter connected with the administration of the Act; and also in regard to—
 - (a) design, erection or position of any aerial ropeway or of any work appurtenant thereto;
 - (b) the addition to, or the alteration or closure of an aerial ropeway;
 - (c) the variation of the character of any ropeway or of the mode of use thereof;
- (ii) to conduct inspection of aerial ropeways and appurtenances—
 - (a) at the initial stage, before the sanction is granted for its operation under sub-section (1) of section 10 of this Act;
 - (b) subsequently at least once in a year; and
 - (c) on such other occasions as may be directed by the State Government;

to ensure that the ropeway is fit for public traffic, and no danger is involved in its use.”

8. In section 13 of the principal Act—

Amendment
of section 13.

- (i) in the heading after the word “Inspectors”, the words “and Expert Committee” shall be added; and
- (ii) after the word “Inspector”, the words “or as the case may be to the members of the Expert Committee”, shall be added.

9. In section 18 of the principal Act, the words “and minimum” shall be omitted.

Amendment
of section 18

10. For the existing section 20 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

Substitution
of section 20.

“20. When any accident occurs in the course of working an aerial ropeway, the promoter shall, without unnecessary delay, send notice of the accident to the State Government and to the Inspector; and the promoter’s servant-in-charge of the station on the aerial ropeway nearest to the place at which the accident occurred, or where there is no station, the promoter’s servant-in-charge of the section of the aerial ropeway on which the accident occurred shall, with the least possible delay, give notice of the accident to the magistrate of the district in which the accident occurred and to the officer-in-charge of the police station within the local limits of which it occurred or to such other magistrate and police officer as the State Government may appoint in this behalf and shall also, if the accident is attended with loss of human life or serious physical injury to any human being, send information to the nearest dispensary”.

11. After section 20 of the principal Act, the following section 20-A shall be added, namely:—

Insertion of
section 20-A.

“20-A. *Rescue operations.*—If the State Government incurs any expenditure during any rescue operation, the promoter shall be liable to pay the expenditure incurred by the State Government and in case the promoter fails to pay the whole or part of it, it shall be recoverable as an arrears of land revenue.”

12. In section 27 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (e), the following clause (ee) shall be added, namely:—

Amendment
of section 27.

“(ee) for regulating the qualifications of the staff employed for running and maintaining the aerial ropeway;”.

13. In section 32 of the principal Act, in sub-section (2)—

Amendment
of section 32.

- (i) for clause (a), the following clauses (a), (aa) and (aaa) shall be substituted, namely:—

“(a) the qualifications and experience of the structural Engineer under section 5 ;

(aa) the powers, functions and duties of an Inspector appointed under section 11;

(aaa) the constitution of the Expert Committee under section 12-A and terms and conditions of the appointment, qualifications and experience of its members;” and

- (ii) in clause (d), the words “and minimum” shall be omitted.

14. In section 33 of the principal Act, for words "two hundred", the words "five thousand" and for the word "fifty", the words "five hundred" shall be substituted.

15. In section 36 of the principal Act, the existing section shall be renumbered as sub-section (1), and thereafter the following sub-section (2) shall be added, namely:—

"(2) If the promoter does anything or omits to do anything, mentioned in section 33, in relation to an aerial ropeway with intent or with knowledge that such act or omission is likely to endanger the safety of any person travelling or being upon the aerial ropeway, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one month but may extend to five years."